

**परीक्षा नियंत्रक कार्यालय**  
**स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर**

क्रमांक: स्केराकृविवि / परीक्षा / ग्रुप.4 / 2022-23 / 2213 - 15

दिनांक 17.03.2023

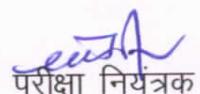
निविदा सूचना

परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु कम्प्यूटर कार्य हेतू उच्च कुशल श्रमिक की आवश्यकता हेतू मोहरबन्द निविदा निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती है जिसका व्योरा निम्न प्रकार है :-

कार्य का विवरण	का अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत (रु.)	निविदा शुल्क (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की तिथि
कम्प्यूटर कार्य हेतू उच्च कुशल श्रमिक	06	09.00 लाख	500.00	18,000.00	27.03.2023 दोपहर 12.00 बजे तक	27.03.2023 अपराह्न 2.00 बजे तक	27.03.2023 अपराह्न 3.00 बजे तक

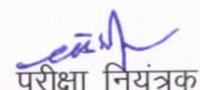
निविदा प्रपत्र निविदा शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट परीक्षा नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के नाम देय प्रस्तुतकर प्राप्त किया जा सकता है।

आंशिक या पूर्ण निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। निहित समय तथा तारीख के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी कारणवश निम्नांकित तिथियों को राजकीय अवकाश घोषित होने पर अगला कार्य दिवस मान्य होगा।

  
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् वित्त-नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. प्रभारी अधिकारीए सिमका स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विश्वविद्यालय एवं लोक उपायन की वेब साईट पर जारी करावे।
3. सूचना पट्ट, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

  
परीक्षा नियंत्रक

**परीक्षा नियंत्रक कार्यालय**  
**स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर**

**कम्प्यूटर कार्य हेतु नियम व शर्तें**

(बिडदाताओं से अनुरोध है कि बिड प्रस्तुत करने से पूर्व बिड के समस्त नियम, शर्तें व निविदा प्रपत्रों का पूर्ण अध्ययन कर लें)

1. कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु दर अनुबंध, अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा जिसे कार्य सन्तोषजनक की स्थिति में आपसी सहमति से तीन माह या नये अनुबंध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है।
2. निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि तथा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा पूर्णतः निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदादाता का राज्य कर विभाग / जी.एस.टी / पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। निर्णायक स्थिति में इन प्रमाणों का मूल प्रतियों से सत्यापन किया जाएगा।
4. निविदादाताओं को किसी राजकीय विश्वविद्यालय/राजकीय विभाग/राजकीय बोर्ड/शिक्षा बोर्ड या समकक्ष शैक्षणिक/प्रशासनिक संस्थाओं में इसी प्रकार की सेवा प्रदान करने का गत पाँच वर्षों में कम से कम 2 वर्ष का एकल अनुभव होना चाहिए।
5. निविदादाता द्वारा आधार कार्ड व आयकर विभाग से जारी पैन कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
6. निविदा के साथ निविदा कार्य लागत के 2 प्रतिशत के बराबर की राशि बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रूप में Controller of Examination के नाम बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। राजस्थान में पंजीकृत एस.एस.आई फर्मों के लिए प्रतिभूति राशि का आधा प्रतिशत (1/2) प्रतिशत देय है। इस लाभ हेतु फर्म को निदेशक उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर से कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
7. निविदा के साथ प्रस्तुत निविदा/शर्तों का नियम आदि सहित समस्त प्रमाण व संलग्नक स्वप्रमाणित (Self attested) होने चाहिए। जिसमें हस्ताक्षर के साथ-साथ फर्म की मोहर (Stamp) लगी होनी चाहिए।
8. निविदादाता को निविदा के साथ निम्नानुसार अपने बैंक का विवरण भी देना होगा :—
  - अ. बैंक व शाखा का पूर्ण नाम व पता :—
  - ब. बैंक खाता संख्या :—
  - स. बैंक का IFSC कोड नम्बर :—
  - द. बैंक खाते का प्रकार (सेविंग/करंट) :—
9. निविदादाता को ₹ 100/- के नॉन ज्यूडिसियल (स्टाम्प पर) शपथ-पत्र देना होगा कि "फर्म/संस्था किसी भी विभाग राजकीय/सार्वजनिक विभाग/उपक्रम से काली सूची में नहीं है एवं फर्म/ संस्था के विरुद्ध कोई राजकीय बकाया नहीं है तथा फर्म/संस्था निविदा की शर्तों का पूर्ण पालन करेगी। फर्म द्वारा नियमों व शर्तों के उल्लंघन पर फर्म नियमानुसार पेनल्टी की भागी होगी।

10. कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान विश्वविद्यालय करेगा। (ई.पी.एफ. तथा ई.एस.आई. का नियोक्ता का अंशदान भारत सरकार के नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा)।
11. कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु सेवा प्रदाता से अनुबंध होने के पश्चात भी उच्च कुशल श्रमिक की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
12. उपलब्ध करवायी जा रही सेवाओं हेतु रखे गये उच्च कुशल श्रमिकों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार या इनके अधीनस्थ विभागों की पी.एफ., ई.एस.आई. या अन्य कोई राशि देय होती है तो उसका भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा ही किया जाएगा। गत भुगतान के दस्तावेज आगामी भुगतान से पूर्व परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अनुबंध की अवधि में श्रम कानून की पूर्णतः पालना हो।
13. सेवा प्रदाता के कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक हेतु प्रस्तुत प्रथम बिल/बिलों के सम्पूर्ण भुगतान को विश्वविद्यालय द्वारा “रिस्क कवरेज” के रूप में जमा किया जावेगा। इस राशि का भुगतान बिना ब्याज सन्तोषजनक सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात किया जावेगा।
14. सेवा प्रदाता सेवाओं को किसी अन्य को हस्तान्तरित या सबलेट नहीं कर सकेगा अन्यथा उसके अनुबंध को निरस्त कर निविदा सुरक्षा राशि व रिस्क कवरेज जब्त कर ली जावेगी।
15. कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक को समय—समय पर केन्द्र/राज्य सरकार आदि के अन्तर्गत देय न्यूनतम पारिश्रमिक/वेजेज, सवैतनिक अवकाश एवं अन्य वैधानिक भुगतान की समस्त जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता की ही होगी व विश्वविद्यालय आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आवश्यक दस्तावेजों की मांग कर सकता है, जो उपलब्ध कराने होंगे।
16. सेवा प्रदाता द्वारा समय पर कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति की वसूली प्रति उच्च कुशल श्रमिक राशि का 110 प्रतिशत के आधार पर संबंधित कार्यालय द्वारा मासिक बिल से वसूल की जावेगी।
17. सेवा प्रदाता कार्य आदेश जारी होने पर जिस तिथी से कम्प्यूटर सम्बन्धित कार्य करवाया जाना है, उस तिथी से उक्त कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध करवाने आवश्यक होंगे। अन्यथा प्रति दिवस 1000 रुपये जुर्माना किया जायेगा, जो सेवा प्रदाता के बिलों या प्रतिभूति राशि से वसूल किया जाएगा।
18. जॉब कार्य हेतु अनुमोदित राशि का भुगतान सेवा प्रदाता को ही किया जावेगा। सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त उच्च कुशल श्रमिक इस कार्यालय से किसी भी प्रकार के भुगतान दावा मांगने के अधिकारी नहीं होंगे। इन्हें किसी भी प्रकार के दावे या भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा ही देय होंगे।
19. संवेदक द्वारा नियोजित उच्च कुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जाएगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित उच्च कुशल श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। उच्च कुशल श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जाएगा।
20. सेवा प्रदाता को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त उच्च कुशल श्रमिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा करवाना होगा। जिसमें नियोजित उच्च कुशल श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होंगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे उच्च कुशल श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जाएगा।

21. उक्त कार्य हेतु उपलब्ध करवाए गये किसी भी उच्च कुशल श्रमिक के कार्य छोड़ने की स्थिति में भी सेवा प्रदाता को तुरन्त दूसरा उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध करवाना होगा।
22. उपलब्ध करवाये गये उच्च कुशल श्रमिक के किसी गैर जिम्मेदाराना या गैर कानूनी कार्य जैसे (चोरी, अश्लीलता, नशा, जुआ आदि) में लिप्त पाये जाने पर उस उच्च कुशल श्रमिक की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता एजेन्सी की होगी। ऐसे उच्च कुशल श्रमिक के विरुद्ध की गई किसी प्रकार की कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही पर देय क्षतिपूर्ति का भुगतान भी सेवा प्रदाय एजेन्सी द्वारा ही देय होगा।
23. सेवा प्रदाता एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि कम्प्यूटर कार्य हेतु उपलब्ध करवाये जा रहे व्यक्ति का चाल-चलन व चरित्र अच्छा हो।
24. अनुमोदित सेवा प्रदाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे उच्च कुशल श्रमिक की सूची उपलब्ध करवानी होगी जिसमें निम्न प्रारूपनुसार पूर्ण जानकारी देनी होगी –

क्र.सं.	उच्च कुशल श्रमिक का नाम	पूर्ण पता	मोबाइल नं.	आधार कार्ड नं.	बैंक का नाम व ब्रान्च	खाता संख्या	नवीनतम फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8

25. निविदा सूचना में वर्णित विवरण व RTPP ACT & Rule अनुसार पात्रता पूरी करने वाले योग्य बोलीदाता ही उक्त निविदा के लिए पात्र होंगे।
26. सफल बोली दाता को नियमानुसार उनके द्वारा प्रस्तुत दरों के आधार पर सम्पूर्ण कार्य के एक वर्ष की राशि का 2.5% प्रतिभूति राशि (Bid Performance Security) के रूप में रूपये 500 के नानज्युडिशियल स्टांप (NJS) पर अनुबंध के साथ प्रस्तुत करनी होगी। उक्त प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी। ईएमडी राशि का समायोजन कर लिया जाएगा।
27. सफल बोली दाता द्वारा प्रतिभूति राशि व अनुबंध पत्र दर स्वीकृति आदेश की दिनांक से निर्धारित समयावधि (15 दिवस) में प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उनकी निविदा सुरक्षा राशि जब्त की जा सकेगी।
28. सफल बोलीदाता से अनुबंध करने से पूर्व उनके मूल लाइसेन्स का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
29. सफल सेवाप्रदाता को अनुबंध के साथ विश्वविद्यालय में एक अंडरटेकिंग (100 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर) अनिवार्य रूप से जमा करवाकर कार्य बिल प्रतिमाह प्रथम कार्य दिवस पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
30. प्रस्तुत किए गए बिलों से वैद्यानिक कटौतियाँ टी.डी.एस., जी.एस.टी., व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जाएगी।
31. उपलब्ध करवाये गये उच्च कुशल श्रमिकों के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रतिलिपि परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में उपलब्ध करवाना आवश्यक है।
32. कम्प्यूटर कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों का सेवा प्रदाता एजेन्सी को उनका प्रमुख नियोक्ता (Principal employer) माना जावेगा। किसी भी प्रकार के सामान्य या न्यायिक विवाद के लिए सेवा प्रदाता एजेन्सी ही जिम्मेदार होगी।

33. अनुबंधित सेवा प्रदाता द्वारा सन्तोषजनक सेवाएं प्रदान न करवाने या सेवा प्रदान करवाने में असफल रहने की स्थिति में उनकी सेवायें निरस्त करते हुये सुरक्षा राशि व रिस्क कवरेज राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त करते हुये निविदादाता की रिस्क व कास्ट पर द्वितीय न्यूनतम दरदाता फर्म या अन्य एजेन्सी से उक्त कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाय एजेन्सी की होगी।
34. विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध बिना किसी कारण बतायें भी निरस्त किया जा सकतोक है। किन्तु ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि लौटा दी जाएगी।
35. सेवा प्रदाता द्वारा दी जा रही सेवाओं का बिल प्रत्येक माह की एक तारीख को संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसका भुगतान कार्यालय द्वार सेवा प्रदाता के बैंक खाते में होगा।
36. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत शर्त/सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
37. समस्त कानूनी कार्यवाही किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने कि स्थिति में बीकानेर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भी करनी होगी, अन्य न्यायालय में नहीं।
38. सेवा अनुबंध अवधि में किसी प्रकार के विधि वाद की समस्त जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
39. अपील अधिकारी
- अ. प्रथम अपील अधिकारी – कुलपति, स्वाक्षराकृविवि, बीकानेर
  - ब. द्वितीय अपील अधिकारी – शासन सचिव कृषि विभाग, जयपुर
40. निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा के साथ चाहे गये प्रमाण पत्र व शुल्कों के प्रमाण उपलब्ध करवा दिये गये हैं।
41. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी, /स्पष्टीकरण निविदा प्रकाशन के सात दिवस में किसी भी कार्य दिवस या कार्यालय समय पर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
42. अ. निविदा दाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा जमा करने से पूर्व निविदा संबंधी समस्त नियमों/शर्तों व निविदा प्रपत्रों को पूर्ण अध्ययन कर लें।  
 ब. निविदा जमा करने से पूर्व निविदादाता समस्त निविदा प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर व फर्म की मोहर अंकित करेगा।
43. उपरोक्त उल्लेखित शर्तों के अलावा सेवा प्रदाता पर RTPP Rules 2013 व RTPP Act. 2012 के अनुरूप सभी नियम, धाराएं, /उपधाराएं लागू होगी।
44. माननीय कुलपति/निम्न हस्ताक्षरकर्ता को निविदा या निविदा के किसी भी भाग को स्वीकार या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
45. वितीय प्रस्ताव में एक से अधिक निविदा दाताओं की समान दरें प्राप्त होती हैं तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय गुणावगुण के आधार पर एक योग्य निविदादाता का चयन करेगा एवं कार्य आबंटन किया जाएगा जिसे सभी निविदा दाताओं को स्वीकार्य होगा।
46. निविदादाता का राजस्थान राज्य का मूल निवासी एवं राजस्थान राज्य में उसका स्थाई कार्यालय होना चाहिए।
47. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
48. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

49. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
50. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिक्रित रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
51. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
52. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।
53. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औघोगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
54. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
55. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती हैं तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को कमइंत कराने की कार्यवाही करेगी।
56. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती हैं तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
57. समयावधि बढ़ाने व घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

**परीक्षा नियंत्रक कार्यालय**  
**स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर**

**निविदा**

**1- Name and Address of Bidder :-**

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	GST की राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कम्प्यूटर सम्बोधित कार्य हेतु उच्च कुशल श्रमिक	06	रु. 333 प्रति दिन 8658.00 प्रति माह		12%	3.25%			

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में समुचित प्रविष्टियां ही बोलीदाता द्वारा भरी जा सकेंगी)  
 (निविदा दरें उपरोक्त दी गई सारणी में अंकित करें)

शून्य/ऋणात्मक दरें या पैसो में दरें स्वीकार नहीं की जायेगी। जिनकी दरें शून्य/ऋणात्मक/पैसो में होगी वे अपात्र होंगे।

**Note :-**

1. Total amount includes service charges, GST, ESI, EPF and all other Charges/taxes/financial liabilities payable by the contract holder.
2. The rates quoted in above bid will be treated as final.

**Signature of Bidders with Seal**

**Controller of Examination**

## **Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

### **Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

## Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

### Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ..... for procurement of ..... in response to their Notice Inviting Bids No.....

Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

## **Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is \_\_\_\_\_

The designation and address of the Second Appellate Authority is \_\_\_\_\_

### **(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

### **(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

### **(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

**(6) Fee for filing appeal**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No.  
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement  
Act, 2012

Appeal No ..... of .....

Before the ..... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii). Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal.....

..... (Supported by a.....)

affidavit)

7.

Praye

Place .....

Date .....

Appellant's Signature

## Annexure D : Additional Conditions of Contract

### 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

### 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

### 3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.